

न्यूज़ ब्रीफ

बिहार बजट सत्र में गुंजा एनईईटी छात्रा की मौत का मामला, मैथिली ठाकुर ने मांगा इंसाफ



नई दिल्ली, एजेंसी | भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की विधायक मैथिली ठाकुर ने सोमवार को कहा कि वे बिहार विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को सक्रिय रूप से उठा रही हैं। यह कदम पहली बार चुने गए विधायकों के लिए आयोजित ब्रीफिंग के बाद उठाया गया है। एएनआई से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि राज्यपाल ने कई बातों का जिक्र किया और बताया कि बिहार पिछले कुछ वर्षों में कैसे विकसित हुआ है, पहले कैसा था और अब कैसे बेहतर हुआ है। उनके भाषण की एक प्रति अभी भी मेरे पास है, जिसमें बिहार की वर्तमान स्थिति के बारे में उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़े भी शामिल हैं।

मैथिली ठाकुर ने आगे कहा कि आज सभी कार्यवाही समझाई गई और यह भी बताया गया कि हमें हर कार्यदिवस पर उपस्थित रहना होगा। यह इसलिए समझाया गया क्योंकि इस बार कई विधायक पहली बार चुने गए हैं, इसलिए उन्हें अलग से निर्देश दिए गए हैं। ठाकुर ने आगे कहा कि वह प्रतिदिन प्रश्न प्रस्तुत कर रही हैं, क्योंकि सांसदों और विधायकों को चौदह दिन पहले प्रश्न प्रस्तुत करने होते हैं, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े सभी मुद्दों को उठाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन प्रश्न प्रस्तुत करके अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी मुद्दों को उठा रही हूँ, क्योंकि हमें चौदह दिन पहले प्रश्न प्रस्तुत करने होते हैं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के सभी मुद्दों को उठाऊंगी।

‘व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर नहीं रोकी जा सकती पूरी चुनाव प्रक्रिया’, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी | किसी एक व्यक्ति की शिकायत के कारण चुनाव की प्रक्रिया को आसानी से न तो रोका जा सकता है और न ही टाला जा सकता है। अगर किसी को चुनाव से जुड़ी कोई व्यक्तिगत शिकायत है, तो उसका अंतिम और एकमात्र उपाय चुनाव याचिका दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट के जुलाई 2025 के एक अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनाया। हाईकोर्ट ने उस आदेश में निर्वाचन अधिकारी को एक व्यक्ति को चुनाव चिन्ह देने और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने को कहा था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई की।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ने या चुनाव को चुनौती देने का अधिकार कानून से मिलता है, इसलिए इसका इस्तेमाल उसी कानून के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट को व्यक्तियों के पक्ष में आसानी से अंतरिम राहत नहीं देनी चाहिए और पूरे राज्य में बिना किसी बाधा के चुनाव कराने चाहिए, क्योंकि यह जनता के हित में है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और दोहराया कि किसी एक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर चुनाव प्रक्रिया नहीं रोकी जा सकती। कोर्ट ने बताया कि उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने 12 जिलों में दोबारा पंचायत चुनाव करने की अधिसूचना जारी की थी।

जन्म उत्सव में एक साथ श्लोक पाठ का बना नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

गुजरात की धरा ने दिया है, मानव कल्याण और सनातन का संदेश : मुख्यमंत्री डॉ. यादव



• भोपाल संवाददाता

भोपाल | मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गुजरात की धरती भारत सहित अनेक राष्ट्रों में धर्म, आध्यात्म, सनातनी परम्परा, मानव कल्याण और सेवा मूल्यों को चेतना से जोड़ने का कार्य कर रही है। इस धरा से कभी महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसी विभूतियों ने राष्ट्र को योगदान दिया, वहीं अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह इस परम्परा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज सऊदी अरब सहित अबूधाबी और अमेरिका में स्वामी नारायण अक्षर धाम के पारम्परिक हिन्दू मंदिर और विश्व के अनेक देशों में 600 से अधिक मंदिरों का निर्माण उल्लेखनीय है। सत्संगदीक्षा जैसे शास्त्रसम्मत ग्रंथ की रचना और हजारों सेवाभावी नवयुवान संतों का निर्माण सनातन की परम्परा को ऊँचाइयों दे रहा है। यह गर्व की बात है कि महंत स्वामी महाराज की जीवन यात्रा की जड़ें मध्यप्रदेश से भी जुड़ी हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को गुजरात के वडोदरा में पूज्य महंत स्वामी महाराज की 92वीं जन्म वर्षगांठ पर उनके दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्वामी को जन्म दिवस की बधाई देते हुए उनके शतायु होने की कामना की और आशा व्यक्त की कि आने वाले वर्षों में स्वामी जी का जन्म शताब्दी समारोह अधिक भव्य रूप में आयोजित होगा। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वडोदरा एक नगर नहीं बल्कि उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है जहाँ भक्ति के साथ सेवा की सुदीर्घ दीक्षित हो रहे बच्चे भी वंदन अभिनंदन के पात्र हैं।

रूप में आयोजित होगा। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वडोदरा एक नगर नहीं बल्कि उस सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है जहाँ भक्ति के साथ सेवा की सुदीर्घ परम्परा है। इस धरती से गुरु के उस संदेश

का प्रसार हो रहा है, जो भगवान स्वामी नारायण से लेकर पूज्य महंत स्वामीजी के जीवन में अभिव्यक्त होता है। अमृत बरसाने वाली यह धारा निरंतर प्रवाहित रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संत वृंद ईश्वर के रूप में विराजमान रहते हैं। उनकी सामूहिक उपस्थिति बगिया में अनेक पुष्पों के एक साथ खिलने की तरह होती है। अपनी शिक्षाओं से वे बच्चों को आलोकित करते हैं। निश्चित ही यह बच्चे भारतीय संस्कृति को जीवंत करने का कार्य करेंगे। दीक्षित हो रहे बच्चे भी वंदन अभिनंदन के पात्र हैं।

संस्कृत श्लोकों के सामूहिक पाठ का बना नया रिकार्ड

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने महंत स्वामी महाराज के 92वें जन्मजयंती महोत्सव में

15 हजार 666 बच्चों को एक साथ स्वामी जी द्वारा रचित 'सत्संग दीक्षा' ग्रंथ के 315 श्लोकों का पाठ किए जाने को एक उपलब्धि बताया। इस गतिविधि का नया गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड भी बना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री पटेल ने महंत स्वामी महाराज से जनकल्याण के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी जी ने दोनों मुख्यमंत्रियों का पुष्पमाला से अभिनंदन किया। कार्यक्रम में श्री गुणातितानंद स्वामी की अद्भुत महिमा एवं जीवन पर केंद्रित नाटक का मंचन किया गया। इसमें गौड़ साम्राज्य के राजा श्री भगवत सिंह के चरित्र के माध्यम से गुणातितानंद स्वामी के सामाजिक और धार्मिक कार्यों की जानकारी दी गई। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव के वडोदरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर गुजरात के मुख्यमंत्री श्री पटेल ने आत्मीय स्वागत किया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर की बात, क्या होने जा रही कोई बड़ी डील?

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। इस बात की जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जिओ गोर ने दी है। इस फोन कॉल के बाद कई तरह की अटकलें लगने लगी हैं। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि दोनों नेताओं के बीच किसी अहम डील पर भी बात हो सकती है। हालांकि, अभी क्या बात हुई है, इसपर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जिओ गोर ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी प्रधानमंत्री मोदी से बात की। स्टे ट्यून्ड... यानी कि आगे और भी जानकारी दी जाएगी। बता दें कि दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब व्यापार समझौते और ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ को लेकर दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार असंतुलन और भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद का हवाला देते हुए भारी 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था।

बता दें कि, हाल ही में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट, जो कि ट्रंप के करीबी सहयोगी हैं, ने कहा था कि अमेरिका, भारत पर टैरिफ कम कर सकता है, क्योंकि नई दिल्ली ने रूस से तेल आयात कम कर दिया है। बाद में, ट्रंप का एक बड़ा दावा भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा।

इससे पहले ट्रंप ने पिछले हफ्ते मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने पहले ही समझौता कर लिया है। भारत इसमें शामिल हो रहा है, और वे ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। तो, हमने समझौते की रूपरेखा तैयार कर ली है।

इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने अहम जानकारी देते हुए बताया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 से 5 फरवरी तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेंगे। इस दौर के दौरान विदेश मंत्री विदेशी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे।

भारत के पांच दिवसीय राजकीय दौरे पर आएंगे सेशेल्स के राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

• नई दिल्ली, एजेंसी

सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी इस साप्ताहिक से पांच दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं। इस दौरान वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी पांच से दस फरवरी तक भारत का राजकीय दौरा करेंगे। हर्मिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यात्रा कर रहे हैं। पिछले अक्टूबर में राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद उनका यह पहला भारत दौरा होगा। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।

मंत्रालय ने बताया कि यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।

एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान में फिर आई 'फ्यूल कंट्रोल स्विच' में खराबी, प्लेन की उड़ान पर लगी रोक



चेक के दौरान पायलट को बाएं इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच में कुछ गड़बड़ी समझ आई। इंजन स्टार्ट करते समय, स्विच दो बार 'रन' पोजीशन में लॉक नहीं हुआ और 'कटऑफ' नहीं हुआ।

नई दिल्ली | एयर इंडिया ने अपने एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान को ग्राउंड कर दिया है। कंपनी ने सोमवार को यह फैसला पायलट द्वारा फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी बताए जाने के बाद लिया गया है। वहीं बोइंग ने कहा है कि वे एयर इंडिया के साथ संपर्क में हैं और इस मामले की समीक्षा में मदद कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, एयर इंडिया के फ्लाइट एआई 132 (बोइंग 787-8) विमान लंदन से बंगलुरु के लिए उड़ानभर रहा था, लेकिन उड़ान से पहले होने वाले फ्लाइट

ऑर चला गया। अगर ऐसी स्थिति में कुछ ख़ास हो जाए, तो उड़ान के दौरान इंजन अचानक बंद हो सकता है। फौरन इस मामले की जानकारी विमानन नियामक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को दे दी गई है।

एयर इंडिया ने इस बारे में कहा है कि उन्हें एक पायलट ने फ्यूल कंट्रोल स्विच में संभावित खराबी की रिपोर्ट दी है। जानकारी मिलते ही उन्होंने विमान को ग्राउंड कर दिया है और ओरिएजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर को जांच के लिए बुलाया है।

तैयार होगा सुरक्षा कवच: ‘चिकन नेक’ में अब जमीन के नीचे दौड़ेगी ट्रेन, पूर्वोत्तर के लिए सरकार का बड़ा प्लान

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली, एजेंसी | पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला रास्ता, जिसे सामरिक तौर पर 'चिकन नेक' कहा जाता है, अब और सुरक्षित और मजबूत होने वाला है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के इस बेहद अहम गलियारे में अंडरग्राउंड रेलवे ट्रेक बिछाने की योजना तैयार की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को बजट आर्बनटन पर चर्चा करते हुए इस बड़े प्रोजेक्ट का खुलासा किया।

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से गुजरने वाला यह रास्ता बहुत संकरा है, जो सामरिक दृष्टि से भारत के लिए संवेदनशील है। रेल मंत्री ने बताया कि इस 40 किलोमीटर लंबे कोरिडोर के लिए विशेष योजना बनाई गई है।

भारतीय रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी विस्तार की दिशा में पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा मील का पथर स्थापित हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलने जा रही है। यह हाई-स्पीड कॉरिडोर न केवल राज्य के भीतर यात्रा के समय को कम करेगा, बल्कि उत्तर-पूर्व (नॉर्थ-ईस्ट) और उत्तर भारत के बीच आर्थिक संबंधों को भी एक नई दिशा प्रदान करेगा।

लोकसभा में तेजस्वी सूर्या की स्पीच पर कांग्रेस का हंगामा, अमित शाह ने एक लाइन में किया चुप

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली, एजेंसी | राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या द्वारा कांग्रेस को चुनौती देने से हंगामा मच गया, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करना पड़ा। तेजस्वी सूर्या ने अपने संबोधन में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उसकी सरकार ने भारत की सभ्यतागत परंपराओं का कभी जिक्र नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को पूर्व राष्ट्रपतियों के भाषणों को पढ़ते हुए ऐसा कोई उदाहरण दिखाने की चुनौती दी।

सूर्या ने आरोप लगाया कि स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर दिए गए संक्षिप्त भाषण के अलावा,

कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में भारत की संस्कृति, परंपरा, सभ्यतागत मूल्यों और परंपराओं का कोई जिक्र नहीं हुआ। यह देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सूर्या ने आगे कहा कि वहीं, 2014 में प्रधानमंत्री ने परंपरा और प्रौद्योगिकी में सुधार का वादा किया था। उस वादे को पूरा करने वाले एकमात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सूर्या की टिप्पणियों का कांग्रेस नेताओं ने तुरंत विरोध किया, जिसके बीच कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने सूर्या का खंडन किया। उन्होंने कहा कि केरल विधानसभा के पूर्व सदस्य पीटी थॉमस ने श्री नारायण गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ कहा है और सूर्या की टिप्पणियों को उनका अपमान बताया।

अरुणाचल प्रदेश की बेटी ने रचा इतिहास, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा

• नई दिल्ली, एजेंसी



नई दिल्ली | अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबाक यानो ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से इतिहास रचते हुए दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवर्गस्ट (अर्जेंटीना) पर 1 फरवरी 2026 को सफलतापूर्वक चढ़ाई की। 22,831 फीट ऊंचा यह पर्वत पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ-साथ अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण माना जाता है।

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. परनाइक (सेवानिवृत्त) ने कबाक यानो को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता व्यक्तिगत विजय के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश की युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह दिखाती है कि अनुशासन, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से कठिन से कठिन लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं।

कबाक यानो का यह अभियान '7-समिट माउंटैनियरिंग एक्सपीडिशन' का हिस्सा है, जिसमें विश्व के सात महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ाई शामिल है।

‘आर्मी को भईया कभी बदनाम नहीं करेंगे’, एमएम नरवणे की किताब पर मचा बवाल

तो राहुल गांधी के बचाव में उतरीं बहन प्रियंका

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूरी सरकार सिर्फ एक लाइन से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि वे संसद में उस लाइन को बोलेंगे और उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा।

• नई दिल्ली, एजेंसी

नई दिल्ली | लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर कांग्रेस अप्रामाणित सोर्स नहीं है तो फिर समस्या क्या है? ऐसे में मोदी सरकार क्यों डर रही है?

‘चीन के सामने 56 इंच की छाती का क्या हुआ’ - कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार इस बात से डरी हुई है कि पूर्व आर्मी चीफ एम एम नरवणे के

हो या मैगजीन। यह किताब का एक अंश है, जो मैगजीन में पब्लिश हो चुका है। इसमें कोई अप्रामाणित सोर्स नहीं है तो फिर समस्या क्या है? ऐसे में मोदी सरकार क्यों डर रही है?

‘चीन के सामने 56 इंच की छाती का क्या हुआ’ - कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार इस बात से डरी हुई है कि पूर्व आर्मी चीफ एम एम नरवणे के

किताब की बातें सामने आई तो देश को बीजेपी के दोनों प्रमुख नेताओं की असलियत पता चल जाएगी और यह भी मालूम पड़ जाएगा कि चीन के सामने '56 इंच की छाती' का क्या हुआ। लोकसभा में गतिरोध बने रहने पर सदन को बैठक दो बार के स्थगन के बाद शाम चार बजकर 10 मिनट पर मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

मोदी सरकार डरी हुई है: राहुल गांधी - सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने संसद परिसर में दावा किया, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और पूरी सरकार सिर्फ एक लाइन से डरी हुई है। वो लाइन मैं संसद में बोलूंगा, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। बाद में उन्होंने एक्स पर लिखा, 'पूर्व

सेना प्रमुख का बयान उजागर कर देगा कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को कैसे निराश किया.'

सेना पर सवाल उठा रहे राहुल गांधी: किरन रिजिजू - रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि वह काल्पनिक बातें करके सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा, 'आप (राहुल गांधी) देश को नीचा दिखाकर क्या कहना चाहते हैं...आप एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। आप ऐसी कोई बात मत बोलिए, जिससे सेना का मनोबल गिरे.'







# एमपी में कंपनी को बिना टेंडर 159 करोड़ का भुगतान

## राशन दुकानों की मशीनों पर हर महीने 1254 रुपए खर्च, 5 साल से जारी मेहरबानी

**भोपाल, नप्र।** मध्य प्रदेश में गरीबों तक पहुंचने वाले राशन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना, अब खुद सवालों के घेरे में है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए हर राशन की दुकान पर लगाई गई पॉइंट ऑफ सेल मशीनें, सरकारी अधिकारियों और एक निजी कंपनी के बीच कथित साठगांठ से कमाई का जरिया बन गई हैं।

एक ही कंपनी, मैसर्स लिंकवेल टेली सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, पर अधिकारी इस कदर मेहरबान हुए कि न केवल उसे पूरे प्रदेश का ठेका सौंप दिया गया, बल्कि एग्रीमेंट समाप्त होने के 5 साल बाद भी लगातार उसे सेवा विस्तार दिया जा रहा है।

इस अवधि में कंपनी को मशीनों के रखरखाव के नाम पर 191 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जबकि आरोप है कि यह पेमेंट गलत तरीके से और ज्यादा दरों पर किया गया है।

**ऐसे शुरू हुई कहानी: 2015 का टेंडर और दो कंपनियों की एंट्री:** मामले की शुरुआत 2015 में हुई, जब मध्य प्रदेश सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को आधुनिक और विश्वसनीय बनाने का फैसला किया। इसके लिए बाॅयोमेट्रिक पहचान को अनिवार्य किया गया, ताकि सही हितग्राही को ही उसका हक मिल सके। मध्य प्रदे़श स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से प्रदेश भर की राशन दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाने और उनके



रखरखाव के लिए एक टेंडर जारी किया।

यह टेंडर ‘बिल्ड-ऑन-ऑपरेट’ मॉडल पर आधारित था, जिसका मतलब था कि चुनी गई कंपनियों को खुद मशीनें खरीदकर लगानी थीं और 5 साल के एग्रीमेंट के दौरान उनके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। इस 5 साल की अवधि में होने वाले भुगतान में मशीनों की लागत, स्थापना व्यय और रखरखाव का खर्च शामिल था।

यह काम दो कंपनियों मैसर्स लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और डीएसके को मिला, जिन्होंने प्रदेश को आधे-आधे हिस्से में बांटकर काम शुरू किया।

## मेट्रो - 100 से ज्यादा मकान-दुकानें हटेंगे

**सिंधी कॉलोनी से डीआईजी बंगला चौराहे तक की मकान व दुकानें आएंगी जद में**

**भोपाल, नप्र।** सुभाष नगर से एम्स तक के प्रोयोरिटी कारीडोर पर मेट्रो शुरू करने के बाद बोगदा पुल से करोंद के रूट का काम तेज कर दिया गया है। जिसके तहत सिंधी कॉलोनी से डीआईजी बंगला चौराहे तक संकरी सड़क किनारे बनी दुकानें और मकानों को हटایा जाना है। जिसके लिए बैरगढ़ एसडीएम रविशंकर राय ने भू-अर्जन का काम शुरू कर दिया है।

यहां पर 100 से अधिक दुकानें और मकान हटाए जाने हैं। जिसको लेकर शुक्रवार को उत्तर विधायक आतिफ अकील इस रूट का अंडग्राउंड कराने की मांग को लेकर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से मिले। इसके पहले सांसद आलोक शर्मा भी शहरी क्षेत्र में मेट्रो रूप को



## भोपाल वाटर स्पोर्ट्स हब:छोटे तालाब की लहरों पर पल रहा वर्दी का सपना



**भोपाल, नप्र।** भोपाल वॉटर स्पोर्ट्स हब बन रहा है। आर्मी, नेवी, बीएसएफ समेत अन्य एजेंसियों में स्पोर्ट्स कोटे से होने वाली भर्तियों के ट्रायल की तैयारी के लिए 15 राज्यों के खिलाड़ी इन दिनों छोटी झील पर कयाकिंग, कैनोइंग, रोइंग में हुनर आजमा रहे हैं। प्रयागराज से आए राज और भुवनेश्वर कहते हैं, पिछले चार महीने से यहां यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। प्रयागराज में नदियां तो हैं, लेकिन भोपाल जैसी सुविधा नहीं है।

**भोपाल इसलिए पहली पसंद:** शांत जल, लंबा वाटर स्ट्रेच और सुरक्षित वातावरण। सबसे अच्छी

प्रेक्टिस लोकेशन। यहां राज्यों के खिलाड़ियों को आपस में भी खिलाते हैं। इससे एक-दूसरे की क्षमता पता चलती है। एमपीकेसीए के सचिव मयंक ठाकुर के अनुसार यहां सेलेक्शन ट्रायल्स भी होते हैं। हर साल यहां से लगभग 150 अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। यूपी पुलिस का सेलेक्शन ट्रायल भी भोपाल में हुआ।

**इन राज्यों के खिलाड़ी:** मप्र कयाकिंग-कैनोइंग एसो. के अध्यक्ष पीएस बुंदेला के अनुसार मणिपुर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी सहित कई राज्यों के खिलाड़ी यहां अभ्यास करते हैं।

### छात्राओं पर वार, आरोपी गिरफ्त से दूर, पुलिस फुटेज के भरोसे

**भोपाल, नप्र।** भोपाल में गुरुवार रात 10:30 से 11 बजे के बीच एक सिरफिरे ने 3 छात्राओं पर चाकू से हमला कर दिया था। घटना हुए 24 घंटे से होने के बाद भी पुलिस अभी तक उसका पता नहीं लगा सकी है। हमला करने वाला आरोपी अभी भी खुलेआम बाहर घूम रहा है। यही नहीं पुलिस अभी तक आरोपी की पहचान भी नहीं कर सकी है। फिलहाल पुलिस की पूरी जांच सिर्फ सीसीटीवी फुटेज पर टिकी है। एसीपी गोविंदपुरा अदिति भावसार ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है। फिलहाल उसे ट्रैक किया जा रहा है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी ने सुनसान इलाके में मिली छात्राओं को अपना निशाना बनाया है। पीड़िताओं ने बताया कि आरोपी ने पहले उनपर चाकू से हमला किया। इसके बाद आरोपी कुछ दूर बाइक से जाता था। कुछ सेकंड के बाद आरोपी वापस उनके पास लौटता था। भीड़-इकट्ठा होने पर आरोपी मौके से भाग जाता था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आरोपी अपनी बाइक पर ही बैठा रहता था। सोनागिरी सेक्टर-ए में एक छात्रा जब घर के बाहर टहल रही थी। आरोपी बाइक से आया और किसी नुकिली चीज से हमला कर दिया था। छात्रा की कमर में चोट आई थी।

### घोटाले के बाद एक कंपनी का एकाधिकार

सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2019 में इस व्यवस्था में एक बड़ी सेंधमारी सामने आई। राजधानी भोपाल में एक ही बाॅयोमेट्रिक पहचान पर कई लोगों को राशन बांटने का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। यह स्पष्ट हो गया कि तकनीक को भी धोखा दिया जा सकता है। इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए डीएसके कंपनी का एग्रीमेंट रद्द कर दिया और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया। यहां से कहानी में एक नया मोड़ आया। नियमों के अनुसार, डीएसके का काम छीनने के बाद खाली हुए आधे प्रदेश के लिए एक नया टेंडर जारी किया जाना चाहिए था। लेकिन अधिकारियों ने ऐसा करने के बजाय, डीएसके का पूरा काम बिना किसी नए टेंडर के सीधे लिंकवेल टेलीसिस्टम्स को सौंप दिया। इस तरह, जो कंपनी पहले आधे प्रदेश में काम कर रही थी, वह रातों–रात पूरे मध्य प्रदेश की मालिक बन गई। इस निर्णय पर सफाई देते हुए तत्कालीन उप सचिव बी. के. चंदेल ने दलील दी थी, केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि राशन का वितरण बाॅयोमेट्रिक पहचान सत्यापित करने के बाद ही किया जाए। यदि इसके बिना राशन बांटा जाता है, तो केंद्र उसकी प्रतिपूर्ति नहीं करता। साथ ही, गरीबों के लिए राशन का वितरण एक दिन भी नहीं रोक़ा जा सकता। इसलिए, उस समय जो मौजूदा विकल्प संभव था, उसे अपनाया गया।

**एक लाइन का सहारा, 6 बार एक्सटेंशन:** अधिकारियों की यह दलील शायद उस तात्कालिक स्थिति के लिए जायज हो सकती थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह पूरी प्रक्रिया को सदिग्ध बनाता है। 2020 में लिंकवेल कंपनी का 5 साल का मूल एग्रीमेंट समाप्त हो गया। इसके बाद एक नई, पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

2020–21 : कोरोना महामारी का हवाला देकर कंपनी को सेवा विस्तार दे दिया गया।

2021–22 : एक बार फिर कोरोना को कारण बताकर टेंडर नहीं निकाला गया।

2022–25 : जब कोरोना का प्रभाव समाप्त हो गया, तब भी नई निविदा जारी करने के बजाय, हर साल एक ही लाइन लिखकर कंपनी का ठेका बढ़ाया जाता रहा टेंडर करने में समय लग रहा है, इसलिए वर्तमान कंपनी को ही काम करने दिया जाए।

इस एक पंक्ति के सहारे कंपनी को 2025 तक, यानी 5 अतिरिक्त वर्षों के लिए, पूरे प्रदेश का काम मिलता रहा। यह सवाल उठना लाजिमी है कि एक सरकारी विभाग को एक टेंडर प्रक्रिया पूरी करने में 5 साल से अधिक का समय क्यों लग रहा है?

अंडग्राउंड करने की मांग कर चुके हैं। विधायक अकील ने बताया कि पुराने शहर के भोपाल टॉकीज, सिंधी कॉलोनी, डीआईजी बंगला क्षेत्र में घनी आबादी होने के साथ ट्रैफिक का दवाब अधिक होता है। ऐसे में मेट्रो के एलिवेटेड पिलर की वजह से इस सड़क किनारे बनी 100 से अधिक दुकान और मकानों को हटया जाएगा। जिससे स्थानीय लोगों के कारोबार पर असर पड़ेगा। अकील ने कहा कि अंडग्राउंड ट्रेक बनाने से आम लोगों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा।

**एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने की मांग:** अकील ने कहा कि इस रूट पर मेट्रो को अंडग्राउंड करने के साथ एलिवेटेड फ्लाईओवर भी बनाया जाना चाहिए, जिससे यहां के ट्रैफिक के दवाब को कम किया जा सके। पिलर पर मेट्रो रूट बनाने से भविष्य में फ्लाईओवर की संभावना भी मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल इस एरिया में आबादी के साथ-साथ वाहनों का दवाब भी बढ़ता जा रहा है। कलेक्टर ने इस मामले को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखने का आश्वासन भी दिया।

**बदलाव मुश्किल, क्योंकि रूट के टेंडर हो चुके हैं:** जानकारों की मान तो एम्स से करोंद तक 16 किमी का रूट तैयार होना है। पूरा रूट कहां पर कैसा रहेगा, ये पहले से तय है। ऐसे में इसमें बदलाव करना मेट्रो अफसरों के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगी।

# बिजली कंपनी की सख्ती..., बकायादार फिर से कनेक्शन जोड़ न लें, इसलिए घर के बाहर बंदूकधारी

**भोपाल, नप्र।** राजधानी में लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकायादारों के खिलाफ बिजली कंपनी ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब केवल नोटिस तक सीमित न रहते हुए कनेक्शन काटे जा रहे हैं और अवैध रूप से दोबारा बिजली कनेक्शन जोड़ने से रोकने के लिए परिसरों पर हथियारबंद सुरक्षा कर्मी तैनात किए जा रहे हैं।

यह अभियान भोपाल सिटी सर्किल के पूर्व और उत्तर संभाग के पुराने शहर क्षेत्रों में चल रहा है। बीते पांच दिनों में कंपनी करीब 97 लाख रुपए की बकाया राशि वसूल चुकी है। सिटी सर्किल के जीएम प्रदीप सिंह चौहान ने बताया कि यह कार्रवाई सभी जोनों में जारी रहेगी।

**दो-स्तरीय वसूली रणनीति:** बिजली कंपनी ने वसूली के लिए दो-स्तरीय रणनीति लागू की है। पहले चरण में बड़े बकायादारों के बिजली कनेक्शन काटे जाते हैं। दूसरे चरण में



संबंधित परिसर पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाते हैं, जिससे अवैध रूप से कनेक्शन जोड़ने या कर्मचारियों के काम में बाधा डालने की कोशिश न हो सके। इसके लिए सेना और विशेष सशस्त्र

बलों से सेवानिवृत्त सुरक्षा कर्मियों को हायर किया गया है। हथियारबंद गार्डों की मौजूदगी से बकायादारों पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बन रहा है। भानुपुर जोन में पहला प्रयोग- इस रणनीति का पहला प्रयोग भानुपुर जोन में किया गया। जोन मैनेजर महेश कोली के अनुसार, बकायादार उपभोक्ताओं के घरो पर सुरक्षा गार्ड और लाइन कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सख्त निगरानी के चलते पांच उपभोक्ताओं से ही लगभग पांच लाख रुपए की बकाया राशि की वसूली संभव हो सकी।

इन पर हुई कार्रवाई- अभियान के तहत मो. नफीस (बकाया लगभग 97,258 रुपये), उमा कुशवाह (लगभग 1.26 लाख रुपये), मो. रिजवान (लगभग 47 हजार रुपये), पूजा विश्वकर्मा (लगभग 64 हजार रुपये) और मीरा बाई (लगभग 35 हजार रुपये) जैसे उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की गई है।

### गैस त्रासदी:भारतीय दोषी कुरैशी की मौत की पुष्टि

**भोपाल, नप्र।** भोपाल गैस त्रासदी के भारतीय दोषियों के मामले में सीबीआई ने भोपाल कोर्ट में युनियन कार्बाइड प्लांट के सुपरवाइजर की डेथ वैरिफिकेशन रिपोर्ट पेश की है। जिसमें बताया गया है कि भारतीय दोषी एसआई कुरैशी की 26 दिसंबर 2025 को नागपुर में मौत हो गई है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र महाराष्ट्र शासन की ओर से जारी किया गया है। एसआई कुरैशी के मौत के बाद 7 भारतीय दोषियों में से 4 की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने एसआई कुरैशी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उसे अभिलेखागार में जमा कराने का आदेश दिया है। बता दें कि 12 जनवरी 2026 को सुनवाई के दौरान भोपाल कोर्ट में आवेदन लगाया गया था कि दोषी एसआई कुरैशी की नागपुर में मौत हो चुकी है। जिसके वैरिफिकेशन के लिए कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था। इस मामले में फिलहाल एसपी चौधरी, किशोर कामदार और जे मुकंद जिंदा हैं। इनके अलावा केशव महिंद्रा, केवी शेट्टी, एसआई कुरैशी और विजय प्रभाकर गोखले की मौत हो चुकी है।

## प्रदेश में बढ़ा रात का तापमान

### बड़े शहरों में पारा 12 डिग्री के ऊपर, दतिया-खजुराहो में घना कोहरा, ग्वालियर-उज्जैन सहित कई जिलों में बारिश

मुरैना, दतिया, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, नोमच, मंदसौर, आगर-मालवा और राजगढ़ जिलों में आंधी और बारिश का अलट आरंभ किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, सागर, विदिशा, उज्जैन और रतलाम में बादल छाप रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24

घंटे तक प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरा और बादल बने रह सकते हैं, जिससे ठंड के साथ-साथ दिन-रात के तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच प्रदेश भर में माघ पूर्णिमा मनाई गई। इस दौरान नर्मदा के तटों पर लोगों ने स्नान कर दान-पुण्य के काम किए।

### पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम का असर

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के सक्रिय होने से यह स्थिति बनी है। 2 से 5 फरवरी के बीच इसका असर ज्यादा रहेगा, जिससे 10 फरवरी तक कहीं-कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही जेट स्ट्रीम हवाओं के कारण प्रदेश में सर्द हवाएं चल रही हैं और दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

### सिस्टम लौटने पर बढ़ेगी ठंड

पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी और बारिश के बाद जब यह सिस्टम वापस लौटेगा, तब प्रदेश में ठंड का एक और दौर आ सकता है। दिन-रात के तापमान में गिरावट के आसार हैं। शनिवार को ग्वालियर, रीवा और दतिया में घना कोहरा रहा, जबकि 20 से अधिक जिलों में मध्यम कोहरा छाया रहा। न्यूनतम तापमान के लिहाज से छतरपुर का खजुराहो सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है।



## ॥ संपादकीय ॥

## आम आदमी की आकांक्षाओं पर कितना खरा है बजट?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 को एक ओर जहां सरकार के घटक ढलों द्वारा विकसित भारत का बजट और बदलते भारत की राजनीतिक-आर्थिक प्राथमिकताओं तथा सरकार की दीर्घकालिक सोच का आईना बताया गया है, वहीं विपक्ष द्वारा इसे पूरी तरह दिशाहीन बजट करार दिया गया है। वैसे निर्मला सीतारमण ने लगातार नौवीं बार बजट पेश कर संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। सवाल यह नहीं है कि बजट कितना बड़ा है या कितने नए आंकड़े पेश किए गए हैं बल्कि यह है कि क्या यह बजट महंगाई से जुड़ा रहे आम नागरिक के वर्तमान को कुछ राहत देता है और भविष्य के लिए भरोसेमंद आधार तैयार करता है? बजट के तमाम महत्वपूर्ण प्रावधानों का आकलन किया जाए तो यह बजट विकास, निवेश, बुनियादी ढांचे, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की स्पष्ट झलक तो दिखाता है लेकिन इसके साथ ही इन्फ्लेमें कई ऐसे खाली स्थान भी हैं, जो आम आदमी और विशेषकर किसान, निम्न आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए निराशा पैदा करते हैं। सरकार ने इस बार तात्कालिक लोकेतुभावन उपायों से दूरी बनते हुए दीर्घकालिक क्षमता निर्माण पर जोर दिया है। यह दृष्टिकोण आर्थिक रूप से समझदारी भरा हो सकता है लेकिन लोकतंत्र में बजट का मूल्यांकन केवल भविष्य के सपनों से नहीं, वर्तमान की चुनौतियों से भी होता है।

शिक्षा और रोजगार को जोड़ने वाला ‘एग्युकेशन-टू-एम्प्लॉयमेंट’ मॉडल सरकार की उस सोच को सामने लाता है, जो कक्षा और कार्यस्थल के बीच की खाई को पटने का दावा करती है। पहली नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए 15,000 रुपये का डीबीटी बोनस और एक करोड़ इंटरशिप की घोषणा निश्चित रूप से आकर्षक लगती है। यह कदम युवाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की दिशा में सकारात्मक है। लेकिन यहां भी सबसे बड़ा प्रश्न क्रियावन्वयन का है। क्या ये इंटरशिप वास्तविक कोशल और स्थायी रोजगार की ओर ले जाएंगी या फिर यह योजना सस्ते श्रम तक सीमित रह जाएगी? भारत पहले भी कई बार योजनाओं के आकर्षक नाम और बड़े लक्ष्यों के बावजूद जमीनी स्तर पर कमजोर क्रियावन्वयन का अनुभव कर चुका है।

‘रिक्ल इंडिया 2.0’ के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसी उभरती तकनीकों को क्षेत्रीय भाषाओं में सिखाने की योजना डिजिटल डिवाइड को कम करने की दिशा में अहम कदम है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी युवाओं के लिए यह तकनीकी दुनिया में प्रवेश का द्वार खोल सकता है लेकिन प्रशिक्षकों की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और उद्योग-सहयोग के बिना यह पहल भी सीमित असर तक सिमट सकती है। शिक्षा बजट को लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव सराहनीय है लेकिन बढ़ती छात्र संख्या, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और शोध की जरूरतों के सामने यह राशि अपर्याप्त प्रतीत होती है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट राहत और माफूसी का मिश्रण है। आयकर दरों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन आयकर पगालों को सरल बनाने की दिशा में घोषणा अप्रत्यक्ष की गई है। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, कर व्यवस्था को जटिल छूटों के जाल से निकालकर सरल और पारदर्शी बनाना, ताकि उपभोग बढ़े और अर्थव्यवस्था में मांग का संचार हो। यह दृष्टिकोण आर्थिक सुस्ती के दौर में उपयोगी हो सकता है।

सर्वकार ने कुछ चुनिंदा वस्तुओं और क्षेत्रों में कर कटौती कर राहत देने की कोशिश की है। कैसर और म्युमेह जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं का सस्ता होना निसंदेह करोड़ों परिवारों के लिए जीवनरक्षक कदम है। मोबाइल फोन, ईवी बैटरी और सौर पैनलों पर रियायतें हरित ऊर्जा और डिजिटल इंडिया को गति देने के साथ-साथ तकनीक को आम आदमी की पहुंच में लाने का प्रयास हैं। जूते, कपड़े और कुछ घरेलू उपकरणों के सस्ते होने से मध्यमवर्गीय खपत में हल्की तेजी आ सकती है लेकिन दूसरी ओर शराब, खनिज और स्क्रैप पर बड़े शुल्क से उत्पादन लागत बढ़ने और अंततः उपभोक्ता कीमतों पर असर पड़ने की आशंका भी बनी हुई है। सबसे बड़ा झटका शेयर बाजार में देखने को मिला। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर बड़े पक्स ने खुदरा निवेशकों की धारणा को कमजोर किया और बजट के दौरान बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे यह संकेश गया कि सरकार सहात्मक गतिविधियों पर सख्ती चाहती है लेकिन इसके दुष्परिणाम अल्पकाल में निवेशकों और बाजार की स्थिरता पर पड़े। यह बजट महंगाई और निवेश के मोर्चे पर एक तरह का विरोधाभास प्रस्तुत करता है, एक ओर खपत बढ़ाने की कोशिश, दूसरी ओर निवेश भावना को झटका।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय सरकार की विकास रणनीति का सबसे मजबूत संकेत है। सात हार्ड-स्पीड रेल कंरेडोरे, जिनमें मुंबई-पुणे और दिल्ली-वाराणसी जैसे मार्ग शामिल हैं, भारत की कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय विकास की तत्वीर बदल सकते हैं। बेहतर परिवहन से उद्योग, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और रियल एस्टेट को नई गति मिल सकती है। टियर-2 और टियर-3 शहरों पर फोकस शहरीकरण के अंस्तुतुन को सुधारने की दिशा में सही कदम है। हालांकि, बुनियादी ढांचे पर खर्च का लाभ आम आदमी तक पहुंचने में समय लगता है और तात्कालिक रूप से निर्माण सामग्री की कीमतों में बढ़ोतरी महंगाई का दबाव बढ़ा सकता है। एमएसएमई और व्यापार जगत के लिए बजट में नई संजीवनी दिखाई देती है। 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रेथ फंड छोटे उद्यमों को पूंजी की कमी से उबार सकता है। महिलाओं के लिए मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करना महिला उद्यमिता को वास्तविक आर्थिक ताकत देने की दिशा में अहम कदम है। टैक्निकल टेक्स्टाइनल पर विशेष फोकस भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थान दिला सकता है और ‘मेक इन इंडिया’ को व्यावहारिक आधार दे सकता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह बजट ऐतिहासिक कहरा जा सकता है क्योंकि पहली बार कंटेेंट फ़िपटर्स और क्रिप्टिव्इ इकोनॉमी को औपचारिक मान्यता दी गई है। ‘रेल’ और ‘रियल’ इकोनॉमी के बीच की दीवार लगभग गिर चुकी है। डिजिटल कंटेेंट, गेमिंग, एनीमेशन और एग्युकेशनल प्लेटफॉर्म को एमएसएमई जैसा दर्जा मिलने से युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। हालांकि बौद्धिक संपदा संरक्षण, आय की स्थिरता और नियमन जैसे सवाल भविष्य की बड़ी चुनौतियाँ बने रहेंगे। स्वास्थ्य और तकनीक के मोर्चे पर ‘बायो-फार्मा 2.0’ और सेमीकंडक्टर मिशन पर जोर भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक सोच को दर्शाता है। दवा परीक्षण और अनुसंधान के लिए 1,000 टेस्टिंग साइट्स का नेटवर्क दवाओं की लागत कम कर सकता है। सेमीकंडक्टर निर्माण में आत्मनिर्भरता भारत को वैश्विक तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत बनाएगी। रक्षा बजट में 15 प्रतिशत की वृद्धोतरी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है लेकिन नई नीतिगत घोषणाओं के अभाव में बाजार की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकीं।

इस पूरे बजट की सबसे बड़ी कमी किसानों को लेकर किसी ठोस और नई घोषणा का न होना है। कृषि क्षेत्र अभी भी महंगाई, लागत और आय की अनिश्चितता से जुड़ा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना समग्र विकास अधूरा रहेगा, यह सच्चाई इस बजट में अपेक्षाकृत कम झलकती है। कुल मिलाकर, बजट 2026-27 संतुलित प्रयास माना जा सकता है। यह न तो लोकतुभावन है और न ही कठोर सुधारवादी। सरकार ने भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए दिशा स्पष्ट की है लेकिन महंगाई, रोजमर्रा का खर्च और आय की सुरक्षा जैसी आम आदमी की तात्कालिक चिंताओं पर सीधी राहत सीमित है। यह बजट आम नागरिक को तुरंत सुकून देने के बजाय धैर्य रखने की सलाह देता है। आने वाले समय में इसका मूल्यांकन इस बात से होगा कि इसके वादे कितनी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ जमीन पर उतरते हैं। अब असली परीक्षा बजट भाषण की नहीं बल्कि उसके प्रभावी क्रियावन्वयन की है।

- योगेश कुमार गोयल (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

# भारत ने बिछाई बड़ी कूटनीतिक बिसात तो सौदेबाजी की मेज पर भागता हुआ आया अमेरिका

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अमेरिका यात्रा ऐसे समय हो रही है जब वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा और व्यापारिक खींचतान एक दूसरे में उलझ चुकी हैं। जयशंकर की यह यात्रा आपूर्ति श्रृंखला, दुर्लभ खनिज, रक्षा सहयोग और व्यापार समझौते पर नए संतुलन की तलाश है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रबियो की पहल पर आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में जयशंकर की भागीदारी इस बात का संकेत है कि आने वाले दशक की शक्ति राजनीति खनिज, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा के इर्द गिर्द घूमेगी।

### जयशंकर की यात्रा सात महीने बाद

#### उनकी पहली द्विपक्षीय अमेरिका यात्रा है।

#### पिछली यात्रा उस समय हुई थी जब अमेरिका ने भारत पर कड़े शुल्क नहीं लगाए थे। इन महीनों में

#### समय हुई था जब अमेरिका ने भारत पर

#### कड़े शुल्क नहीं लगाए थे। इन महीनों में

#### बहुत कुछ बदल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति

#### डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद

#### शुल्क को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया।

#### अमेरिकी राष्ट्रपति

#### डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद

#### शुल्क को हथियार की तरह इस्तेमाल किया

#### गया।

जयशंकर की यह यात्रा सात महीने बाद उनकी पहली द्विपक्षीय अमेरिका यात्रा है। पिछली यात्रा उस समय हुई थी जब अमेरिका ने भारत पर कड़े शुल्क नहीं लगाए थे। इन महीनों में बहुत कुछ बदल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद शुल्क को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और रूस से तेल खरीद पर दंडात्मक शुल्क ने संबंधों में कड़वाहट घोली। अब संकेत मिल रहे हैं कि वाशिंगटन नरमी दिखा सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूस से तेल खरीद घटने पर अतिरिक्त शुल्क हटाने का रास्ता है। साथ ही वेनेजुएला से तेल खरीद फिर शुरू करने की अनुमति का संदेश भी दिया गया है। यह सब केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि वार्ता की मेज पर सौदेबाजी के पत्ते हैं।

दिलचस्प यह है कि इसी बीच भारत ने 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता पूरा कर लिया। इसने अमेरिका



को यह संदेश दिया कि नई दिल्ली विकल्प तलाशने में सक्षम है। अटलांटिक परिघट से जुड़े विशेषज्ञ मार्क लिंस्काट का आकलन है कि भारत यूरोप समझौता अमेरिका भारत व्यापार वार्ता को तेज कर सकता है। साफ है कि वाशिंगटन भारत को खोना नहीं चाहता। वैसे भी भारत और अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व की हालिया बातचीत और सार्वजनिक बयानों से यह आभास भी मजबूत हो रहा है कि दोनों देश लंबित व्यापार समझौते को अब अधिक देर तक टालना नहीं चाहते। पिछले महीनों में फोन पर हुई वार्ताओं, मंत्रिस्तरीय संपर्क और समान हितों पर दिए गए जोर से यह संकेत मिलते हैं कि माहौल को जानबूझकर सकारात्मक बनाया जा रहा है। ऐसे में जयशंकर की अमेरिका यात्रा को केवल खनिज या सामरिक चर्चा तक सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे संभावित व्यापार समझौते की राह साफ करने वाली पहल के रूप में भी समझा जा रहा है। कूटनीतिक गलियारों में यह धारणा बन रही है कि यदि इस यात्रा में मुख्य अड़चनों पर सहमति का रास्ता निकलता है तो यह आगे की औपचारिक वार्ता के लिए हरी झंडी जैसा होगा, जिसके बाद मोदी सरकार अंतिम राजनीतिक स्वीकृति देकर समझौते पर मुहर लगा सकती है। यानी यह दौरा भविष्य के बड़े आर्थिक फैसले की भूमिका भी लिख सकता है।

हम आपको यह भी बता दें कि अपनी यात्रा से पहले जयशंकर ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। उनके साथ अमेरिकी संसद के सदस्य जिमी

पैटोनिंस, माइक रोजर्स और एडम स्मिथ भी मौजूद रहे। बातचीत में व्यापार, रक्षा सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, हिंद प्रशांत क्षेत्र और यूक्रेन संघर्ष जैसे विषय शामिल रहे। यह केवल शिष्टाचार भेंट नहीं बल्कि जमीन तैयार करने वाली बातचीत थी। गोर ने भारत को अमेरिका का अहम भागीदार बताया और साझा सामरिक हितों पर जोर दिया। साथ ही अमेरिकी संसदीय दल की जनवरी में नई दिल्ली यात्रा भी रक्षा तकनीक सहयोग, सह उत्पादन और सह विकास पर केंद्रित रही। संदेश साफ है कि रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधों की रीढ़ बन सकता है।

अब इस पूरे घटनाक्रम को भारत के केंद्रीय बजट की घोषणाओं से जोड़कर देखिये। मोदी सरकार ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज संपन्न राज्यों में दुर्लभ खनिज गलियारे बनाने का प्रस्ताव रखा है। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और निर्माण को बढ़ावा देने की योजना सीधे उसी दिशा में जाती है जिस पर अमेरिका और उसके सहयोगी काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर अभियान के लिए ये खनिज अनिवार्य हैं। बैटरी भंडारण के लिए लिथियम आयन कोश निर्माण, सौर कांच के लिए सोडियम एंटीमोनेट, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आयातित सामान पर मूल शुल्क छूट, मिश्रित सीएनजी पर उत्पाद शुल्क गणना से जैव गैस को बाहर रखना और बैटरी भंडारण परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर सहायता को पांच गुना बढ़ाना दिखाता है कि भारत ऊर्जा और प्रौद्योगिकी की नई दौड़ के

### जनरल नॉलेज

## भारत के बजट से किन देशों को होगा तगड़ा नुकसान, जानें सबसे ज्यादा कौन परेशान?



**वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट पेश किया है. आइए जानते हैं कि इस बजट से किन देशों को नुकसान हुआ.**

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया. हालांकि ज्यादातर ध्यान घरेलू प्राथमिकताओं पर रहा लेकिन बजट ने भारत की सीमाओं से परे भी काफी मजबूत संकेत दिए हैं. विदेशी सहायता आवंटन में बदलाव का कई पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार देशों पर सीधा असर पड़ा है. आइए जानते हैं कि इस बार के बजट से किन देशों को तगड़ा नुकसान हुआ है.

बांग्लादेश को सबसे बड़ा झटका - सभी देशों में बांग्लादेश भारत के नवीनतम बजट से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है. बांग्लादेश को वित्तीय सहायता में लगभग 50% की कटौती की गई है. यह पिछले साल के 120 करोड़ से घटकर सिर्फ 60 करोड़ रह गई है. इस भारी कटौती को ढाका में हाल के राजनीतिक बदलावों के बाद तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ा जा रहा है. यह कटौती एक साफ राजनयिक संदेश देती है. ऐसा इसलिए क्योंकि बांग्लादेश पारंपरिक रूप से भारतीय विकास सहायता का एक बड़ा लाभार्थी रहा है.

इरान के चाबहार बंदरगाह के लिए शून्य आवंटन - भारत के इरान के साथ जुड़ाव में एक और

## गांधी जी को नमन

देश के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अविस्मरणीय योगदान से पूरी दुनिया परिचित है। वे जीवन पर्यंत देशवासियों के लिए आदर्श नायक बने रहे। अहिंसा की राह पर चलते हुए देश को अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलाने वाले गांधी जी ने पूरी दुनिया को अपने विचारों से प्रभावित किया था। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर कई किताबें भी लिखी, जो हमें आज भी जीवन की नई राह दिखाती हैं क्योंकि उनके ये अनुभव, उनका अहिंसा का सिद्धांत, उनके विचार आज भी उतने ही सार्थक हैं, जितने उस दौर में थे। उनके जीवन के तीन महत्वपूर्ण सूत्र थे, जिनमें पहला था सामाजिक गंदगी दूर करने के लिए झाड़ू का सहारा। दूसरा, जाति-पाति और धर्म के बंधन से ऊपर उठकर सामूहिक प्रार्थना को बल देना। तीसरा, चरखा, जो आगे चलकर आत्मनिर्भरता और एकता का प्रतीक माना गया। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप अगर दूसरों पर डालते हैं तो उसकी कुछ बूँदें आप पर भी गिरती हैं। वे कहते थे कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं

### टेक्नोलॉजी

## कंप्यूटर को रिस्टार्ट और शट डाउन करने से क्या होता है? जानें दोनों में क्या है फर्क

अगर आप विंडोज कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि इसमें शटडाउन और रिस्टार्ट के ऑप्शंस मिलते हैं. ये दोनों ही कंप्यूटर के ऑपरेशन को शट डाउन करने के काम आते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है. शट डाउन जहां आपके कंप्यूटर को बंद कर देता है, वहीं रिस्टार्ट एक पल के कंप्यूटर को बंद कर रिस्टार्ट कर देता है. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इन दोनों में बड़ा अंतर है. आइए जानते हैं कि इन दोनों में और क्या-क्या अंतर है और कब किस ऑप्शन को यूज करना चाहिए.

शट डाउन से क्या होता है? - विंडोज के बहुत पुराने वर्जन में शट डाउन और रिस्टार्ट का काम एक जैसा ही होता था, लेकिन विंडोज 8

बल्कि उसके चरित्र से होती है। दूसरों की तरफकी में बाधा बनने वालों और नकारात्मक सोच वालों में सकारात्मकता का बीजारोपण करने के उद्देश्य से ही उन्होंने कहा था कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को ही अंधा बना देगी। लोगों को समय की महत्ता और समय के सही सदुपयोग के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति समय को बचाते हैं, वे धन को भी बचाते हैं और इस प्रकार बचताई ही क्योंकि उनके ये अनुभव, उनका अहिंसा का सिद्धांत, उनके विचार आज भी उतने ही सार्थक हैं, जितने उस दौर में थे। उनके जीवन के तीन महत्वपूर्ण सूत्र थे, जिनमें पहला था सामाजिक गंदगी दूर करने के लिए झाड़ू का सहारा। दूसरा, जाति-पाति और धर्म के बंधन से ऊपर उठकर सामूहिक प्रार्थना को बल देना। तीसरा, चरखा, जो आगे चलकर आत्मनिर्भरता और एकता का प्रतीक माना गया। गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप अगर दूसरों पर डालते हैं तो उसकी कुछ बूँदें आप पर भी गिरती हैं। वे कहते थे कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं

लोगों को जीवन में हर दिन, हर पल कुछ न कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करते हुए गांधी जी कहा करते थे कि आप ऐसे जिएं, जैसे आपको कल मरना है लेकिन सीखें ऐसे कि आपको हमेशा जीवित रहना है। उनकी बातों का देशवासियों के दिलोदिमाग पर गहरा असर होता था। महात्मा गांधी के विचारों में ऐसी शक्ति थी कि विरोधी भी उनकी तारीफ

किए बगैर नहीं रह सकते थे। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस समय हमारे देश के अधिकांश नेता इस बात के पक्षधर थे कि अब देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का बिल्कुल सही मौका है और इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हुए उन्हें इस समय देश में बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ देना चाहिए। दरअसल उन सभी का मानना था कि अंग्रेज सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त रहने के कारण भारतवासियों के इस आंदोलन का सामना नहीं कर पाएगी और आखिरकार उसे उन्हे इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के समक्ष सिर झुकाना ही पड़ेगा और इस प्रकार अंग्रेजों को भारत को स्वतंत्र करने पर बड़ी आसानी से विवश किया जा सकेगा। जब यही बात गांधी जी के सामने उठाई गई तो उन्होंने अंग्रेजों की मजबूरी से फायदा उठाने से साफ इन्कार कर दिया। हालांकि उस दौरान अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी ने आन्दोलन तो जरूर चलाया, लेकिन उनका वह आन्दोलन सामूहिक न होकर व्यक्तिगत स्तर पर किया गया आन्दोलन ही था।

तो बंद हो जाती हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा विंडोज कर्नेल बंद नहीं होता. यह डिस्क पर सेव रहता है और आप अगली बार जब सिस्टम ऑन करते हैं तो आपको इसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता और यह तुरंत बूट हो जाता है. रिस्टार्ट करने पर क्या होता है? - दूसरी तरफ जब आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो यह विंडोज कर्नेल समेत सारी प्रोसेस को बंद कर देता है. इसका मतलब है कि जब कंप्यूटर दोबारा बूट होगा तो आपको एकदम क्लीन स्टार्ट मिलती है. हालांकि, इसे बूट होने में थोड़ा समय लगता है. इसलिए जब आप कोई अपडेट या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कोई एरर रिजॉल्व करना चाहते हैं तो सिस्टम को रिस्टार्ट करना चाहिए.

लिए तैयारी कर रहा है। 2030 तक पांच सौ गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा और 2047 तक सौ गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य भारत की नई सामरिक दिशा है। निजी भागीदारी खोलने वाला परमाणु ऊर्जा कानून भी

इसी कड़ी का हिस्सा है। सच यह है कि दुनिया नए शीत युद्ध जैसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां गोलियों से ज्यादा खनिज, चिप और ऊर्जा की आपूर्ति श्रृंखला ताकत तय करेगी। जयशंकर की यात्रा को केवल कूटनीतिक दौरा समझना भूल होगी। यह भारत की बहुस्तरीय चाल है। एक ओर अमेरिका से तनाव घटना, दूसरी ओर अपने हितों पर अडिग रहना, और साथ साथ यूरोप, रूस तथा अन्य साझेदारों के साथ संतुलन बनाए रखना आसान नहीं। पर भारत अब रक्षात्मक नहीं, सौदेबाज की मुद्रा में दिख रहा है।

अमेरिका को भी समझना होगा कि शुल्क की लाठी से साझेदारी नहीं चलती। यदि वह भारत को सचमुच चीन का विकल्प बनाना चाहता है तो भरोसा, प्रौद्योगिकी साझेदारी और बाजार पहुंच देनी होगी। भारत के लिए भी संदेश साफ है कि आत्मनिर्भर खनिज और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाए बिना कोई सामरिक स्वायत्तता संभव नहीं।

बहरहाल, जयशंकर की कूटनीति की खासियत यही है कि वे मुस्कान के साथ कठोर संदेश देते हैं। अब देखना यह है कि वाशिंगटन इस संकेत को कितना समझता है। अभी जो तत्वीर उभर रही है वह बताती है कि नई दिल्ली ने खेल समझ लिया है और चाल चल दी है।

- नीरज कुमार दुवे (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)



यूरोप-भारत ट्रेड डील से बांग्लादेश बेचैन,  
मोहम्मद यूनुस ने EU से जल्द FTA के लिए  
लगाई गुहार, कपड़ा कारोबार में तबाही का डर

## एजेंसी ढाका

भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच प्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) ने बांग्लादेश को बचैन कर दिया है। देश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूसुफ ने यूरोपीय यूनियन से जल्द ट्रेड डील करने की गृहाण लगाई है। मोहम्मद यूसुफ की दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि 'मुख्य सलाहकार ने लगातार ड्यूटी-प्री एक्सेस सुनिश्चित करने के लिए EU के साथ जल्द FTA बचाव का आह्वान किया है।' मोहम्मद यूसुफ ने बांग्लादेश में यूरोपीयन यूनियन के राजदूत माइकल मिलर और बांग्लादेश में यूरोपीयन चैंबर ऑफ कॉमर्स (EuroCham) की चेयरपर्सन लुईजा लोपेज से ढाका में मुलाकात की। लोपेज ने कहा कि लेबर बांग्लादेश की सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि 'मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूसुफ ने रिविजर को यूरोपीयन यूनियन के साथ प्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) बातचीत जल्द शुरू करने का आह्वान किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले सालों में मौजूदा ड्यूटी-प्री एक्सेस खत्म होने के बाद बांग्लादेश के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मॉडेल में उसकी यूरोपीय प्रार्थनिकाओं की रक्षा करना जरूरी है।' सरकारी बयान के मुताबिक 'मुख्य सलाहकार ने ये बातें ढाका के स्टेट गेस्ट हाउस जमुना में बांग्लादेश में यूरोपीयन चैंबर ऑफ कॉमर्स (EuroCham) की चेयरपर्सन लुईजा लोपेज की शिफ्टवार मुलाकात के दौरान कहा। इस बैठक में बांग्लादेश में यूरोपीयन यूनियन के राजदूत माइकल मिलर भी शामिल हुए थे। मोहम्मद यूसुफ ने इस दौरान कहा कि 'बांग्लादेश में यूरोपीय निवेश को तेज करने की जरूरत, बांग्लादेश और EU के बीच सुचारु व्यापार संबंधों को तेज से सुनिश्चित किया जाए और देश के कारोबार माहौल को बेहतर बनाने के लिए और सुधारों की जरूरत पर चर्चा की।' यूसुफ ने कहा कि अंतरिम सरकार ने हाल ही में जापान के साथ एक आर्थिक साझेदारी समझौता (EPA) किया है, जिससे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में 7,300 से



ज्यादा बांग्लादेशी उत्पादों के लिए इयूटी-प्री एक्सेस का रास्ता साफ हो गया है।" उन्होंने कहा कि "बांग्लादेश अन्य देशों, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, उसके साथ इसी तरह की बातचीत करने की तैयारी कर रहा है, ताकि भविष्य में EU बाजार में अपने उत्पादों, खासकर रेमेडिड कपड़ों के लिए लगातार इयूटी-प्री एक्सेस सुनिश्चित किया जा सके।" वहीं, यूरोपिये चैयरपर्सन यूरोप लोएज ने कहा कि "बांग्लादेश को तुर्क FTA बातचीत शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि सबसे कम विकसित देश (LDC) का दर्जा खत्म होने के बाद देश EU, जो उसका सबसे बड़ा बाजार है, को अपनी मौजूदा व्यापार प्राथमिकताएं छोड़ सकता है।" भारत-EU प्री डी एमयूटि से पाकिस्तान और बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। बांग्लादेश को यूरोपिय बाजार में इयूटी प्री एक्सेस सुविधा है, उससे बांग्लादेशी कपड़े काफी सस्ते हो जाते हैं। लेकिन अब भारत के पास भी वही सुविधा होगी और बांग्लादेश, भारत के

प्रोडक्शन क्षमता और सप्लाई चेन का मुकाबला नहीं कर पाएगा।  
 बांग्लादेश की ओभी तब सबसे कम विकासित देशों (LDCs) के लिए "एयरथिंगिंग बर्ड अपस्ट्रेड" (EBA) स्क्रीन के तहत बिना किसी टैरिफ के EU को अपने टैरिफ एक्स्पॉर्ट करेगा था। वहीं, भारतीय एक्स्पॉर्ट पर 9% से 12% का टैरिफ लगता था। लेकिन नए FTA के बाद भारतीय टेक्सटाइल, चर्म और समुद्री प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटकर ज़ीरो हो जाएगा। यमि भारत उस बावर्की के मैदान पर मुकाबला करेगा। अपने बड़े कच्चे कपास के बेस और इंड्रोपेटेड सप्लाई के के साथ, भारत बांग्लादेश से कम कीमती पर सामान बेचेगा। 2029 के नवंबर तारीख तक भारत के पास स्थिर, स्थायी जीरो-ट्यूटी एक्सेस होना, जबकि बांग्लादेश पर भारी टेक्स लग सकता है, जिससे उसके प्रोडक्ट्स यूरोपीय खरीदारों के लिए काफी महंगे हो जायेंगे और उसका कपड़ा उद्योग जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसका करीब 50% प्रतिशत से ज्यादा कारोबार भी खत्म हो जाएगा।

पानी रुकने से सहमे पाकिस्तान की UN में भारत  
को गीदड़भभकी, दुनिया से मदद की गुहार

एजेंसी न्यूयॉर्क

पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र (UN) में सिंधु जल संधि (IWT) का मुद्दा उठाया है। यूएन में पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि भारत ने एकतरफा तरीके से सिंधु संधि (IWT) को निलंबित किया है। इस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसके मानवीय, शांति और सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इफ्तिखार ने भारत को गैरदृष्टिकोणों से दूरे हुए कहा कि दिल्ली को इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बीते साल अक्टूबर में पहलवाम के आतंकी हमले के बाद भारत ने घोषणा की थी कि वह पाकिस्तान के साथ 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई IWT को स्थगित कर रहा है। IWT संधि सिंधु बेसिन की नदियों के पानी को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटती है। भारत के कदम से पाकिस्तान के सामने जल संकट पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है। इफ्तिखार अहमद ने शनिवार को यूएन में 'अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संधियों की पवित्रता को बनाए रखने पर सुरक्षा परिषद की अग्रेसर फॉर्मूला बैठक' में बोलते हुए कहा कि IWT को संरक्षित मजबूत जल-बंटवारे वाली संधियों में गिना जाता है। यह कई संकटों



और राजनीतिक तनावों के बावजूद ये कायम रही। लेकिन अब इस पर सन्देह है। इतिहास ने आगे कहा है कि स्थापित जल-बंटवारे की व्यवस्था में स्कावट के मानवीय, पर्यावरणीय और जैविक-सुरक्षा पर गंभीर परिणाम होंगे। भारत का पानी को रोकेना पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के लिए मुश्किल पैदा करती है। लाखों लोगों की जीवन रेखाओं को इस तरह से मुश्किल में नहीं डालना जा सकता है। पाकिस्तानी दूत अहमद ने वाहयारा के डाल संधि द्विपक्षीय चिन्ता नहीं है बल्कि अंतरराष्ट्रीय

एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें एकतरफा निर्लंबन को रोकेना और स्थितियों का जलू करना शामिल है। स्थितियों का पालन किया जाना जरूरी है। पाकिस्तान ने हालिया महीनों में भारत को बार-बार गंदेडुपधकी दी है कि वह अपनी नदियों के प्रवाह को रोकने या मोड़ने नहीं देगा। इस्लामाबाद ने पिछले साल कहा था कि भारत की सरकार से उसके पानी के बहाव को रोकने की किसी भी कोशिश को एकदम से बंद कर दिया जाएगा। वही वह इसे युद्ध की शुरुआत मानेगा।

भारतीयों के लिए एक परीक्षा है। अगर विवादों या संघर्षों को रोकने के लिए बनाई गई संधि की एकतरफा अन्वेषी की जाती है तो कोई भी समझौता वास्तव में राजनीति की सभी प्रकार की चालों से सुरक्षित नहीं है।

असमंद ने आगे कहा कि अमेरिका, विदेशीयकृत क्षेत्र, व्यापार रणियाँ और मानवीय व्यवस्थाएँ सभी अधिक नाजुक हो जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद की राज्यों के एकतरफा निर्णयों को गुनना शामिल है। संधियों की परीक्षा है। पकिस्तान ने हालिया अरब गैर-हथकड़ी की है कि कोई रोकने या मरोड़ने नहीं है।

साल कहा था कि भारत की सुरक्षा को रोकने की किसी भी योजना जाएगा। यानी वह इसे

ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर इजरायल ने साध  
र रही है चुप्पी, क्या है नेतन्याहू का सीक्रेट प्लान

## एजेंसी तेल अवीव

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और सारा दुनिया की नजर अस्थिरित डोनाल्ड ट्रंप के आगले कदम पर है। ट्रंप ने लगातार ईरान को लेकर धमकाने वाला खूब जारी रखा है और तेहरान को जल्द से परमाणु डील के लिए तैयार होने को कहा है। इन सबसे बीच ईरान के कट्टर दुश्मन इजरायल ने आश्चर्यजनक चूप्पी साध ली है। इजरायल के नेतृत्व ने वॉशिंगटन के तेहरान पर हमले की संभावना पर बहुत कम टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और उनकी कैबिनेट ने इजरायल के सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के बारे में सार्वजनिक चर्चा से लगभग दूरी बना रखी है। इजरायली डिफेंस इंटीलेंजेंस के पूर्व अधिकारी डैनी सिफ़ोनीविस इस समय इजरायल के शेनोन सिफ़ोयरी



स्टडीज इंस्टीट्यूट में ईरान के सीनियर रिसर्चर हैं।  
उन्होंने बीबीसी को बताया कि यह चुप्पी बताती है कि  
नेतार्याहू के लिए कितना जरूरी समय है। उन्होंने कहा  
के नेतार्याहू इसे एक सुनहरा मौका मानते हैं, जिसे वे  
गंवाना नहीं चाहते। खासतौर पर खाड़ी में अमेरिका का  
मिश्राल जंगी बढ़ा बैठा है। इजरायली शीप नेटवर्क  
के तौर पर सहमत है कि इस बार वॉशिंगटन को पहल

करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अमेरिकी ज्यादा मजबूत हैं, उनके पास ज्यादा क्षमताएँ हैं और उन्हें कहीं ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी है। हालाँकि, इसरायल चुप जरूर है लेकिन शांत नहीं है और न ही हाथ पर हाथ धरे बैठता है। इस सभ्यता की शुरुआत में इसरायल के मिलिट्री डेटिलिजेंस कर्मी रश्यों को बाइंडर ने वॉशिंगटन में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के साथ बैठक की। इसरायली मीडिया रिपोर्टों में बताया कि इस दौरान निर्रज के अंदर संभावित लक्ष्यों में चचा की गई। सेंट्रिनोविक का मानना है कि नेत्याहुह चाहते हैं कि अमेरिकी बड़े हमले करें जो ईरानी नेतृत्व को खत्म या बहुत कमजोर कर दें। उन्होंने जनवरी की शुरुआत में ट्रंप को ईरान पर कदम पीछे खींचने को कहा था क्योंकि अमेरिकी संभावित कार्रवाइ बहुत सीमित मानी जा रही थी। मध्य पूर्व में अमेरिकी सहयोगी जहां सत्ता परिवर्तन को लेकर चलाती दे रहे हैं कि इससे स्पष्ट अर्थहीन हो सकता है।

डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति में खुली गुंडागर्दी, अमेरिकी विशेषज्ञ ने दुनिया को चेताया, भारत और BRICS को दिए 3 सुझाव

## एजेंसी वॉशिंगटन

अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने अपने देश के हूवमरारों की दुनिया के लिए खराब रविये की तीखी आलोचना की है। सैक्स ने कहा है कि अमेरिकी विदेश नीति कूटनीति के बजाय गैंगेस्टर के गैंग की तरह चलाई जा रही है। अमेरिका दुनियाभर के देशों में सत्ता बढियाने के ऑपरेशन, एकतरफा प्रतिबंध और इधरियों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले फाइनेंस के तौर पर खुली धमकियां दे रहा है। दुनिया और भारत जैसी ताकतों को अमेरिका के इन तौर-तरीकों का विरोध करना चाहिए। द संडे गार्जियन को दिए इंटरव्यू में जेफरी सैक्स ने कई बातें कही हैं। उनका मानना है कि संयुक्त राष्ट्र कमजोर हुआ है क्योंकि दूसरी बड़ी ताकतें अमेरिका की मनमाना का

सामना करने में नाकाम हैं। इससे 1945 के बाद की व्यवस्था खतरे में आ गई है। जैफरी ने गैर-पश्चिमी दुनिया खासतौर से भारत और BRICS देशों से अपील की है कि वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर की रक्षा का काम करें और अमेरिका की टकराव की रणनीतियों में ना फँसें।

जैफरी ने कहा, 'अमेरिका ने यूएन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अभी यह संस्था पूरी तरह खत्म नहीं हुई है लेकिन बहुत देर होने से पहले इसे बचाने की जरूरत है। BRICS को इसके बचाव में एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। इस साल BRICS की अध्यक्षता भारत के पास है। मैं ब्रिक्स के देशों को तीन सुझाव देना चाहता हूं।

पहला- BRICS को एक समूह के तौर पर अमेरिका की एकतरफा नीतियों की निंदा करे और बोर्ड ऑफ पीस जैसी नीतियों को खारिज

कर दे। दूसरा- BRICS को समूह के तौर पर UN सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए भारत और ब्राजील का समर्थन करना चाहिए, ताकि अमेरिकी दबदबे को संतुलित किया जा सके। तीसरा- भारत को ब्वाड छोड़ देना चाहिए, ताकि अमेरिका अपनी चीन विरोधी नीतियों में भारत का इस्तेमाल ना कर सके। डोनाल्ड ट्रंप के वेनेजुएला में हमले और सीनलैंड-ईरान को हमले को धमकियों के सवाल पर जेफरी ने कहा, 'ट्रंप वह कह रहे हैं जो पहले सिर्फ निजी तौर पर या ह्नुपकर बोला जाता था। अमेरिकी विदेश नीति अब एक खुली गुंडागर्दी है। बाकी दुनिया UN के सिद्धांतों पर चलकर और एकजुट होकर अमेरिकी मिलिट्रीवाद के खिलाफ आवाज उठा सकती है। दुनिया को तुरंत इस पर सोचना और अमल करना होगा।'

नेपाल में क्या कर रहे ब्रिटिश खुफिया एजेंसी  
MI-6 के 'जासूस' ? सरकार बनाने-गिराने  
में माहिर, लकी बिष्ट का बड़ा दावा

एजेंसी काठमांडू

नेपाल में ब्रिटेन के कुख्यात उद्योगपति लॉर्ड अशक्रॉफ्ट पिछले कुछ दिनों से मौजूद हैं। हालांकि कबने के लिए ये एक उद्योगपति हैं, लेकिन उनके ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI-6 से गहरे रिश्ते रहे हैं। नेपाल में पिछले साल एक हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व एजेंट लकी बिष्ट ने दावा किया है कि नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले तीन दिनों से एक प्राइवेट जेट मौजूद है, लेकिन नेपाल की सरकार को उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये काफ़ी सनसनीखेज है कि देश के एक बड़े एयरपोर्ट पर एक विमान नहीं है और सरकार को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लकी बिष्ट वो एजेंट हैं, जिन्होंने कई महीने पहले ही नवभारत टाइम्स से बात करके हुए नेपाल में प्रदर्शन होने और सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर दी थी। उनके पास नेपाल की राजनीति को लेकर गहरी समझ है। उन्होंने पिछले दिनों नवभारत टाइम्स से बात करते हुए कहा था कि 'काठमांडू के मेयर बालेन शाह' नेपाल के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। लेकिन अब उन्होंने नया दावा किया है कि MI-6 नेपाल में इन दिनों एक्टिव है। लकी बिष्ट ने एक वीडियो के जरिए दावा किया है कि '28 जनवरी 2026 से सरकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट सैलैक जेट खुदा है और हैरानी की बात ये है कि नेपाल सरकार को इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। आज भी पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा कंट्रोल चीन के पास है। इसी से ब्रिटेन के बिजनेसमैन लॉर्ड अशक्रॉफ्ट नेपाल आए हैं जिन्हें सिर्फ उद्योगपति कहना आधा सच है। ये दुनिया भर में सरकार बनाने-बिगाड़ने में भूमिका निभाते हैं और MI6 के एजेंट हैं।' उन्होंने आगे कहा है कि 'इस वक्त उनकी नजदीकियां केपी ओली से हैं, जिन्हें नेपाल की जनता सता



से बाहर कर चुकी है। 5 मार्च 2026 से नेपाल में दोबारा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे संदर्भदेशीय समर्थ में लॉर्ड अशक्राफ की मौजूदगी सिर्फ इंतज़ाफ़ नहीं लगती। सवाल सवाल है क्या नेपाल की राजनीति के पीछे कोई अदृश्य खेल खेला जा रहा है?" उन्होंने आगे दावा किया है कि "लॉर्ड अशक्राफ एक बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदते हैं, शेयर बाजार को ऊपर-नीचे करते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जब भी किसी देश में चुनाव होने को होते हैं, ये MI6 की तरफ से उस देश में पहुँच जाते हैं। वहाँ की पार्टी को फंड करते हैं।" लकी बिष्ट ने वॉइडयो में दावा किया है कि "किस पार्टी को फंड करना है ये MI6 को पता है। ये बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट डीप का पूरा चीन के कंट्रोल में है। क्योंकि कैंपे ओली की पीढ़ी था। चीन को हमेशा पता होता है कि एयरपोर्ट पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो लॉर्ड अशक्राफ अभी भी नेपाल में हैं। 5 मार्च को नेपाल में इलेक्शन है और ये फिर से उसी सरकार को लेकर आना चाहते हैं, जिसे नेपाल की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया था।" नवभारत टाइम्स सस्की पुष्टि नहीं करता है कि लॉर्ड अशक्राफ को लेकर लकी बिष्ट के दावे में किताम दम है, लेकिन लकी बिष्ट ने नवभारत टाइम्स पर नेपाल को लेकर जो भी दावे किए हैं, वो सच साबित हुए हैं।

अमेरिका ने पाकिस्तान को दिखाई जमीन, ट्रंप को खनिज बॉक्स देने वाले मुनीर को मिनरल्स कॉन्फ्रेंस से किया आउट, जयशंकर को न्योता



एजेंसी इस्लामाबाद

भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने शहबाज ख़ाँगीफ और असीम मुनीर की अमेरिका नीति पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक अब्दुल बासित ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस्लामाबाद को ग्लोबल मिनरल कॉर्पोरेशन का च्योता नहीं भेजा है, जबकि भारत इसमें शामिल होगा। यह इसलिए खबर है क्योंकि बीते साल पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को बॉक्स देते हुए पाकिस्तान में दुर्लभ खनिज खोजने का च्योता दिया था। अब्दुल बासित ने एक वीडियो में कहा है, 'मुनीर ने ट्रंप को बॉक्स में भरकर दुर्लभ मिनरलस ऑफर किए लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को ग्लोबल मिनरलस कॉर्पोरेशन में बुलाया तक नहीं भेजा।' दूसरी ओर अमेरिका ने भारत को बुलावा भेजा है। 4 फरवरी को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस कॉर्पोरेशन के लिए वॉशिंगटन में होंगे। यह इसलिए हैरत में डालता है क्योंकि मिनिरल को लेकर पाकिस्तान का यूएस के साथ एग्रीमेंट हुआ है। वहीं भारत से अमेरिका के संबंध फिलहाल अच्छे नहीं हैं।

पाकिस्तान के आमी चीफ असीम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ ने बीते साल सितंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस दौरान मुनीर ने ट्रंप को बलूचिस्तान के ग़िरफ्तार अर्थ मिनरल्स का बॉक्स दिया था। इस डिब्बे में क़ैप्टन तौर पर वाइटेनेडाइट और मोनाजाइट के खनिज थे। इसके बाद अमेरिका का खनिजों पर पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ। वाइइट हाउस ने ट्रंप की शरीफ और मुनीर के साथ सी मीटिंग के फोटो जारी किए थे। इन तस्वीरों में लकड़ी के डिब्बे वाले फोटो में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। ट्रंप इस डिब्बे को बेहद गौर से देख रहे थे और मुनीर उनको कुछ समझाते देखे थे। इस तस्वीर के बाद माना गया था कि अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान ने अमेरिका को मिनरल्स का लालच देकर फंसा लिया है। पाकिस्तान को अमेरिका की ओर से ग्लोबल मिनरल्स कॉन्फ्रेंस का न्योता ना मेलना दिखाता है कि रंग-बिरंगे पत्थरों को रेयर एरथ्स एलिमेंट्स (REE) बनाने का मिनरल्स का लालच नुभाने का दोष शायद फेल हो गया है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बासिता का दावा अगर सही है तो वह मुनीर और शहबाज दोनों के लिए एक बड़ी चमिंदगी का सबब है।









# शादीशुदा नाना पाटेकर को हो गया था मनीषा से प्यार, किसने की बेवफाई



**नाना पाटेकर काफी पजेसिव थे दोनों के बीच टकराव बढ़ गया और ब्रेकअप हो गया**

कुछ प्रेम कहानियां सिर्फ यादें बनकर रह जाती हैं और उनको कोई नाम नहीं मिल पाता है। ऐसी एक प्रेम कहानी 90 के दशक में शुरू हुई थी जो कि नाना

पाटेकर और मनीषा कोईराला की थी।

बता दें कि फिल्म अग्निसाक्षी की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच रिश्ता शुरू हुआ था। कहा जाता है कि मनीषा कोईराला और नाना पाटेकर एक दूसरे के काफी करीब थे

और कहा जा रहा कि वो शादी के बंधन में बंध सकते हैं। लेकिन नाना पाटेकर उस वक़्त शादीशुदा थे। इससे पहले कि ये मामला कुछ आगे बढ़ता सब खत्म हो गया।

**शादीशुदा थे नाना:** मनीषा कोईराला ने अग्निसाक्षी के बाद फिल्म खामोशी में एक साथ काम किया था। नाना पाटेकर शादीशुदा तो थे लेकिन अपनी पत्नी से अलग रहते थे। उन्होंने 1978 में नीलकांती नाम की महिला के साथ शादी की थी लेकिन दोनों विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। उनके बच्चे थे लेकिन वो अलग ही रहते थे। इस दौरान मनीषा के साथ उनका प्यार परवान चढ़ रहा था। लेकिन बाद में दोनों की खबरें आने लगीं कि सब कुछ सही नहीं है।

कहा जाता है कि नाना पाटेकर मनीषा को लेकर काफी पजेसिव थे और वो नहीं चाहते थे कि मनीषा रिवीलिंग कपड़े पहने। दोनों के बीच टकराव बढ़ गया और ब्रेकअप हो गया। मनीषा कोईराला को लग गया था कि नाना पाटेकर के साथ उनका कोई प्यूर नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है मनीषा कोईराला ने इसलिए नाना को छोड़ा था क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देने से इंकार कर दिया था।

## सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना चाहती हैं आलिया भट्ट

**बोलीं- कई बार मन करता है, लेकिन ऐसा करने से फैस से संपर्क टूट जाएगा**

एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने हाल ही में कहा कि कई बार उनका मन सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट करने का करता है।

एस्कवायर इंडिया को दिए इंटरव्यू में आलिया ने कहा, “कई दिन ऐसे होते हैं जब मैं उठकर सोचती हूँ कि बस सोशल मीडिया डिलीट कर दूँ और सिर्फ एक्टिंग करूँ। बार-बार इस बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहती, लेकिन मुझे यह भी पता है कि ऐसा करने से उन लोगों से संपर्क टूट जाएगा, जिन्होंने शुरू से मेरा साथ दिया है। मैं ऐसा नहीं चाहती।”

बता दें कि आलिया भट्ट देश में सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 86 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।

इंटरव्यू में आलिया ने मां बनने के बाद आए बदलावों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि मां बनने के बाद उनकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह बदल गई है। अब उनकी दुनिया ज्यादातर अपनी बेटी के इर्द-गिर्द घूमती है। आलिया ने कहा, “अब जब पर्सनल लाइफ की बात आती है, तो वह इतनी पर्सनल हो गई है कि उसे शेयर करना थोड़ा मुश्किल लगता है। मेरे फोन की फोटो गैलरी मेरी बेटी राहा

से भरी हुई है। मुझे अपनी तस्वीरें लेने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है।” उन्होंने मां बनने को एक बड़ा बदलाव बताया। आलिया के मुताबिक, इससे न सिर्फ शरीर बदलता है, बल्कि सोच, प्राथमिकताएं और दुनिया को देखने का नजरिया भी बदल जाता है।

बता दें कि आलिया भट्ट और एक्टर रणबीर कपूर ने अप्रैल 2022 में शादी की। उसी साल नवंबर में उनकी पहली बेटी राहा का जन्म हुआ।

आलिया के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही एक्शन थ्रिलर फिल्म अल्फा में नजर आएंगी।

**फोन की फोटो गैलरी बेटी राहा से भरी हुई है**



**किस किसको प्यार करूँ-3 में चहल भी**



**एआई जेनरेटेड पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वायरल**

सोशल मीडिया पर जब से एआई जेनरेटेड फोटो या वीडियो का ट्रेंड शुरू हुआ है तभी से लोग इसे इस्तेमाल करना और इस पर अपने रिएक्शन देना काफी पसंद करते हैं। ऐसा ही एक एआई जेनरेटेड पोस्टर भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिस पर युजवेंद्र चहल भी कमेंट करते नजर आ रहे हैं।

कई लड़कियों के साथ जुड़ चुका है चहल का नाम: यूं तो आए दिनों भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। कभी वह अपने तलाक की वजह से सुर्खियों में रहते हैं तो कभी अपनी निजी जिंदगी और अफेयर्स की अफवाहों की वजह से चर्चाओं में आ जाते हैं। बता दें कि धनाश्री वर्मा से तलाक के बाद युजवेंद्र चहल का काफी लोगों के साथ नाम जोड़ा जाता रहा है। हाल ही में युजवेंद्र चहल और बिग बॉस 13 फेम शेफाली बग्गा को मुंबई के एक रेस्टोरेंट से साथ बाहर निकलते देखा गया था जिसके बाद उनकी डेटिंग की खबरें सामने आने लगीं इससे पहले चहल का नाम RJ महावश के साथ जोड़ा गया था लेकिन जब से दोनों लोगों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया है तभी से उनके ब्रेकअप की खबरें तेजी से फैलीं।

## सनी देओल को स्क्रिप्ट सुनाने मनाली पहुंचे राजकुमार संतोषी ‘घातक 2’ पर बड़ा अपडेट



बॉलीवुड में इन दिनों ‘सीक्वल के ट्रेंड’ की लहर लगातर बढ़ती जा रही है, और इसी कड़ी में अब प्रसिद्ध फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी एक बार फिर से सनी देओल के पास अपना नया प्रोजेक्ट लेकर पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक संतोषी हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंचे हैं, जहां वे सनी देओल को ‘घातक 2’ की कहानी और स्क्रिप्ट सुनाने वाले हैं। वैसे भी ‘गदर 2’ और ‘बॉर्डर 2’ की सफलता के बाद सनी देओल अब इंडस्ट्री के डिमांडिंग एक्टर बन गए हैं।

1996 में रिलीज हुई फिल्म ‘घातक’ बॉलीवुड के उन एक्शन फिल्मों में से एक थी जिसने सनी देओल की छवि को और भी मजबूती दी थी। अब लगभग 30 साल बाद उसी फिल्म के सीक्वल की चर्चा जोरों पर है। राजकुमार संतोषी ने इस सीक्वल के लिए एक ठोस आईडिया तैयार किया है, जिसे उन्होंने सनी को व्यक्तिगत रूप से मनाली में सुनाने का निर्णय लिया है।

सनी देओल फिलहाल हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां मना रहे हैं और ‘बॉर्डर 2’ की जबरदस्त सफलता का आनंद ले रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने अब तक लगभग 300 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर ली है और दर्शकों की ओर से खूब सराहना पा रही है। सूत्रों के अनुसार राजकुमार संतोषी और सनी देओल के बीच इस प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग आज यानी 31 जनवरी 2026 को हो सकती है। इस दौरान संतोषी अपने स्क्रिप्ट को विस्तार से सनी के सामने रखेंगे और उनका फीडबैक जानेंगे। अगर सनी को कहानी पसंद आती है, तो इस सीक्वल की घोषणा जल्द ही हो सकती है।

हालांकि सनी देओल पहले ही साफ कर चुके हैं कि वे सिर्फ इसलिए किसी पुराने क्लासिक का सीक्वल नहीं करेंगे कि पिछली फिल्में सफल रहीं। उनका मानना है कि इस तरह का कदम दर्शकों के साथ धोखा जैसा होगा। इसलिए अगर उन्हें स्क्रिप्ट में वास्तविक दम दिखता है और कहानी उन्हें प्रभावित करती है, तभी वे इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी देंगे।

सनी देओल और राजकुमार संतोषी ने पहले भी कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया है, जैसे ‘घायल’ (1990), ‘दामिनी’ (1993) और ‘घातक’ (1996)। ये फिल्में जबरदस्त चली थीं और आज भी लोगों को बहुत याद हैं।

**सीक्वल को लेकर बन सकती है बात**



## टीवी से बड़े पर्दे तक पहुंचेगी ‘नागिन’



**पौराणिक और फैंटेसी अवतार में दिखेगी नई दुनिया**

एकता कपूर की सुपरहिट फ्रैंचाइजी पर फिल्म बनाने की तैयारी: एकता कपूर का सुपरहिट शो ‘नागिन’ अब टीवी की दुनिया से आगे बढ़कर सिनेमाघरों तक पहुंच सकता है। इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, बालाजी टेलीफिल्म्स इस पॉपुलर फ्रैंचाइजी को फिल्मों के रूप में पेश करने की संभावनाओं पर काम कर रहा है।

2015 में मौनी रॉय और अदा खान के साथ शुरू हुआ ‘नागिन’ देखते ही देखते देश के सबसे चर्चित सुपरनैचुरल शोज में शामिल हो गया। बीते 11 सालों में इस फ्रैंचाइजी के कई सीजन आ चुके हैं और फिलहाल ‘नागिन 7’ टीवी पर ऑन-एयर है। अब मेकर्स इसकी पौराणिक और फैंटेसी दुनिया को बड़े पर्दे पर और भव्य रूप में दिखाने की योजना बना रहे हैं।

‘नागिन 7’ कलर्स टीवी चैनल पर प्रसारित हो रहा है: हालांकि, ‘नागिन’ फिल्म का कॉन्सेप्ट अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बड़े पर्दे पर नागिन का किरदार कौन निभाएगा। टीवी की तरह ही इस रोल के लिए भी लंबा ऑडिशन प्रोसेस रखा जा सकता है, क्योंकि यह प्रोजेक्ट एकता कपूर के बेहद करीब रहा है और वह लुक से लेकर स्टायलिंग तक हर चीज पर खास ध्यान देती हैं।

एकता कपूर इन दिनों कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। उनकी और TVF की थिएट्रिकल फिल्म ‘Vvan’ में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लीड रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा अक्षय कुमार, तब्बू और परेश रावल स्टार होस्ट-कॉमेडी ‘भूत बंगला’ भी 15 मई 2026 को रिलीज होने वाली है।

## ओपनिंग डे पर ‘मर्दानी 3’ की धमाकेदार शुरुआत



**फिल्म ‘बॉर्डर 2’ से मिल रही कड़ी टक्कर**

रानी मुखर्जी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘मर्दानी 3’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर इसे सनी देओल की पहले से मजबूत पकड़ बनाए हुए फिल्म ‘बॉर्डर 2’ से कड़ी टक्कर मिल रही है। सीमित स्क्रीन और बड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद फिल्म ने पहले दिन संतोषजनक शुरुआत दर्ज की है। दर्शकों के बीच रानी के दमदार किरदार को लेकर उत्सुकता साफ नजर रही है। ट्रेड रिपोर्ट्स के

अनुसार, ‘मर्दानी 3’ ने ओपनिंग डे पर 3.80 करोड़ रुपये का कारोबार किया। दिलचस्प बात यह है कि यह कमाई ‘मर्दानी 2’ के पहले दिन के कलेक्शन के बराबर है, जबकि इसने 2014 में आई पहली फिल्म ‘मर्दानी’ के ओपनिंग डे के कलेक्शन (3.46 करोड़) को पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ यह फिल्म रानी मुखर्जी के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्मों की टॉप लिस्ट में शामिल हो गई है।

यशराज फिल्म के बैनर तले बनी इस फ्रैंचाइजी की पहचान सामाजिक मुद्दों पर आधारित सशक्त कहानियों से रही है। पहली फिल्म में मानव तस्करी, दूसरी में एक खतरनाक अपराधी की मानसिकता और अब तीसरी किस्त में समाज की एक नई कड़वी सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की गई है। फिल्म को लेकर दर्शकों और समीक्षकों के बीच चर्चा तेज है।

वहीं दूसरी ओर, ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार मजबूती से टिकी हुई है। आठवें दिन भी फिल्म ने दो अंकों में कमाई करते हुए भारत में 257 करोड़ रुपये से ज्यादा का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ‘मर्दानी 3’ इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में कितनी लंबी रेस तय कर पाती है।



## कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह की अध्यक्षता में समय सीमा की बैठक संपन्न, अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश

• **साधना एक्सप्रेस, नरसिंहपुर**  
नरसिंहपुर\*, कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा पत्रकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर द्वारा विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह नागेश सहित अन्य विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने निर्देशित किया कि निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर 2026 से संबंधित सभी कार्यों को इस सप्ताह तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि अभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों तथा लंबित प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। साथ ही



अभियान के नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने प्रभार क्षेत्र का नियमित भ्रमण करें।

बैठक में अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने किसानों के पंजीयन कार्य में तेजी लाने तथा शेष किसानों का पंजीयन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने 'नरसिंहपुर फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2025' के विजेताओं को वितरित किए पुरस्कार नरसिंहपुर,

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत गजेन्द्र सिंह नागेश ने एक दिसम्बर से 15 दिसम्बर 2025 तक आयोजित 'नरसिंहपुर फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2025' के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस अवसर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राशि के चेक, प्रमाण पत्र एवं उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त करने पर करेली निवासी श्री गोपाल पटेल को 11,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर नरसिंहपुर निवासी श्री पिपुय नेमा को 7,100 रुपये तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर नरसिंहपुर निवासी श्री देव कतिया को 5,100 रुपये की राशि का चेक, प्रमाण पत्र एवं गिफ्ट देकर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता

में चयनित 10 प्रतिभागियों को सात्वना पुरस्कार स्वरूप प्रमाण पत्र एवं उपहार प्रदान किए गए। उल्लेखनीय है कि जिले के पर्यटक, विरासत एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों, स्मारकों, प्राकृतिक संरचनाओं, वनों, नदियों, जलप्रपातों, राष्ट्रीय उद्यानों, गुफाओं एवं धार्मिक स्थलों के फोटोग्राफ का लोकेशन-आधारित डाटाबेस तैयार करने तथा प्रतिभावान फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "नरसिंहपुर फोटोग्राफी प्रतियोगिता 2025" का आयोजन जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद (डीएटीसी), नरसिंहपुर द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया था। प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल 10 श्रेणियों में फोटोग्राफ आमंत्रित किए गए थे, जिनमें वन एवं वन्य जीवन, नदियां एवं जल संरचनाएं, पर्वत एवं घाटियां, सांस्कृतिक एवं विरासत स्थल, प्रकृति पथ, संग्रहालय, धार्मिक स्थल, स्थानीय भोजन एवं व्यंजन, मेले एवं त्यौहार, पर्यटन स्थल, होम-स्टे एवं फार्म-स्टे शामिल थे।

## 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आम जन अधिकार पार्टी ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

• **साधना एक्सप्रेस, मनगावा**  
मनगावा | आम जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता की अगुवाई में सोमवार को पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) मनगावा को 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्र की वर्षों पुरानी जनसमस्याओं के निराकरण की मांग की गई।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से मनगावा में कई वर्षों से निर्मित बस स्टैंड होने के बावजूद बसों का संचालन प्रारंभ न किए जाने का मुद्दा उठाया गया। साथ ही मनगावा से चाकघाट एवं रोवा से हनुमान मार्ग पर सड़कों पर



गोवंश के कारण हो रहे सड़क हादसों पर चिंता व्यक्त करते हुए उचित व्यवस्था की मांग की गई।

इसके अलावा मलकपुर तालाब से अतिक्रमण हटाकर सौंदर्यीकरण कराने, आईटीआई

मनगावा के क्षतिग्रस्त भवन को नए सिरे से निर्माण कराने, लालगांव में मुक्तिधाम के लिए रास्ता निकलवाने, गढ़ बाजार के अंदर अत्यंत खराब स्थिति में पड़ी सड़क की मरम्मत कराने, गढ़ बाजार में अंधूरी पड़ी

नल-जल योजना को शीघ्र पूर्ण कराने की मांग की गई।

वहीं किसानों की सम्मान निधि में पटवारी द्वारा की जा रही हीलाहवाली का भी मुद्दा उठाते हुए पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे।

ज्ञापन सौंपने के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता के साथ रंजेंद्र गुप्ता, डॉ. शैलेंद्र कुमार सोनी, रामेश्वर गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

## भगवान श्री सत्य साई बाबा के दिव्य रथ और चरण पादुका का रोवा जिले में हुआ आगमन



• **साधना एक्सप्रेस, मनगावा**

रोवा 1 फरवरी! प्रशांति निलियम, पुष्टपती आंध्रप्रदेश की

पावन पवित्र वसुंधरा से चल कर साईं रथ और साईं चरण पादुका का मध्यप्रदेश में आगमन हुआ। म.प्र.

के समस्त जिलों में होते हुए दिव्य रथ का रोवा जिले में भी आगमन हुआ। रोवा शहर में भ्रमण उपरांत

ग्राम कोठी, खौर, लक्ष्मणपुर, बदराव, त्योथर और अमिलिकी में दिव्य रथ का भ्रमण हुआ।

मानव मानव में प्रेम स्थापित हो, मानव मूल्यों का प्रचार हो, सेवा व परोपकार की भावना आपस में विकसित हो, इन तमाम उद्देश्यों के साथ दिव्य रथ हर शहर हर गांव में जा रहा है। 'सबसे प्रेम सबकी सेवा' और 'मानव सेवा ही माधव सेवा' जैसे भगवान श्री सत्य साई बाबा के ध्येय वाक्यों को आम जनमानस तक ये दिव्य रथ पहुंचाने का कार्य कर रहा है।

रोवा जिले में आगमन पश्चात सैकड़ों लोगों ने दिव्य रथ का दर्शन एवं भगवान का अनुग्रह प्राप्त किया। विभिन्न स्थानों पर दिव्य रथ का स्वागत किया गया। सम्पूर्ण कार्यक्रम के सफलतम निर्वाहन पर श्री सत्य साई सेवा संगठन के जिलाध्यक्ष प्रदीप निगम एवं समिति संयोजक महेंद्र कुमार चौदहा ने भगवान बाबा एवं समस्त भक्तों के प्रति आभार व्यक्त किया।

## पूर्ण आहुति से हुआ 27 कुण्डीय श्रीराम मानस यज्ञ का समापन

• **साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा**

गाडरवारा\*। क्षेत्र के चौरवगढा ब्लॉक अंतर्गत पुण्य सलिला माँ नर्मदा के पावन तट ग्राम कोंठिया घाट मे माँ नर्मदा जयंती से प्रारम्भ हुआ 28 वां 27 कुण्डीय श्रीराम मानस यज्ञ गत दिवस माघ पूर्णिमा पर पूर्ण आहुति एवं भंडारे के साथ समाप्त हो गया। आयोजन समिति से जुड़े भक्त अमित पटेल से प्राप्त जानकारी के अनुसार माँ नर्मदा पूजन से कलश यात्रा निकालकर यज्ञ प्रारंभ हुआ था इसी दिन सभी ने शाम को दीपदान भी किया। यज्ञ मे प्रतिदिन सुबह 8 से 2 बजे तक हवन पूजन आदि कार्यक्रम हुए एवं पुराणों का पाठ किया गया। इसके अलावा 2 बजे से वीरेंद्र शास्त्री प्रवचन सुनाये गए। अंतिम दिन सभी श्रद्धालुओं ने पूजा



अर्चना के साथ पूर्ण आहुति देकर भंडारे के आयोजन के साथ यज्ञ का समापन किया। विदित हो कि उक्त

आयोजन ब्रम्हदेव आश्रम के परम संत श्री जगत देव दास जी महाराज की प्रेरणा से किया गया जिसमें सभी

दिन बड़ी संख्या मे धर्म प्रेमी श्रद्धालु उपस्थित रहे।

## पीएमश्री खिरका स्कूल में हुआ आयोजन

### वार्षिक महोत्सव में बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुति



• **साधना एक्सप्रेस, गाडरवारा**

गाडरवारा\*। गत दिवस पीएम श्री शासकीय प्राथमिक शाला खिरका साईंखेड़ा में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव मनाया गया। जिसमें विद्यालय के नन्हे मुन्हे बच्चों द्वारा बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती पूजन इसके बाद शालाप्रमुख रामस्वरूप बसेड़िया एवं श्रीमती प्रभावमा, गौरव शुक्ला मनीषा कुचावाहा एवं 5 वी के बच्चों द्वारा सभी मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में देश भक्ति से ओतप्रोत कक्षा पहली की नन्ही बच्चों द्वारा देशभक्ति नृत्य एवं धरती पुकारे

झुमा और वीर हनुमान इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संदीपनी विद्यालय के प्राचार्य श्रीमान चंद्रकांत विश्वकर्मा, भानु राजपूत, आशीष शुक्ला, अजय शंकर तिवारी मनोज राजपूत एवं वार्ड के पार्षद राजेंद्र ठाकुर, बी ए सी शमनीराम मेहरा ने अपनी उपस्थिति प्रदान की एवं अधिक संख्या में अभिभावक गण माता बहनों की उपस्थिति भी सराहनीय रही। मंचीय कार्यक्रम का सफल संचालन स्कूल की शिक्षिका श्रीमती सुषमा तिवारी ने किया एवं आभार रामस्वरूप शर्मा ने किया।

## वाहन रैली और कृषि रथ के माध्यम से किसानों को किया जा रहा है जागरूक

भोपाल | राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में वाहन रैली के माध्यम से किसानों को खेती की नवीन तकनीकों को अपनाकर फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जागरूक किया गया। इसके तहत विभिन्न जिलों में वाहन रैली आयोजित की गई।

धार जिला मुख्यालय पर विधायक श्रीमती नीना वर्मा एवं कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा द्वारा हरी झण्डी दिखाकर किसान जागरूकता वाहन रैली को रवाना किया गया। जिले में किसानों के लिए कृषि एवं कृषि से संबंधित विभागों की योजनाओं का प्रचार-प्रसार कृषि रथ के माध्यम से निरंतर प्रत्येक ग्राम पंचायत में किया जा रहा है।

कृषक कल्याण वर्ष के प्रचार-प्रसार के लिए कृषि रथ के मुख्य आधार स्तंभ:- जैविक खेती एवं प्राकृतिक कृषि क्षेत्रों का विस्तार, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रचार-प्रसार, एकीकृत पोषक तत्व, कीट एवं रोग प्रबंधन, कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय,



फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना,

विभागीय कृषि योजनाओं का प्रचार-प्रसार, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना, ई-विकास प्रणाली अंतर्गत ई-टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था, पराली प्रबंधन आदि विभागीय योजनाओं से जागरूक किया जा रहा है।

सिवनी जिला मुख्यालय पर किसानों को जागरूक करने के लिए मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य किसानों

में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें शासन की विभिन्न कृषक हितैषी योजनाओं से जोड़ना रहा। मोटरसाइकिल रैली में सिवनी विधायक श्री दिनेश राय ने स्वयं मोटरसाइकिल चलाकर सहभागिता की और किसानों का उत्साहवर्धन किया।

बेतूल जिले में किसानों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिला स्तरीय वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधिकारियों

की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर अधिकारियों ने किसानों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, नवाचारों और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने का संदेश दिया। रैली में मोटरसाइकिल, चार पहिया वाहन एवं विभागीय वाहनों के माध्यम से आकर्षक बैनर-पोस्टर लगाकर किसान कल्याण से जुड़े संदेश प्रसारित किए गए। इसी तरह पाटुर्णा जिले में भी किसान मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया।